

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489

www.uvindianews.com

प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह



चक्का जाम : लाल किला, जामा मस्जिद आईटीओ और दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन बंद...P-4

▶ वर्ष : 17 ▶ अंक : 2 ▶ गाजियाबाद, फरवरी, 2021 ▶ मूल्य : 4 रूपया ▶ पृष्ठ : 04 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

कोरोना लाइव

10,815,222
मामले (भारत)

10,509,790
मरीज ठीक हुए

154,956
कुल मौतें

105,926,858
मामले (दुनिया)

भारत में हर चौथा व्यक्ति हो चुका है कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। देश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों का आंकड़ा 1.08 करोड़ है। परंतु, हाल ही में सरकारी एजेंसी की तरफ से कराए गए सीरो सर्वेक्षण के नतीजों से जो संकेत मिले हैं, उसके मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की वास्तविक संख्या सरकारी आंकड़े से कहीं बहुत ज्यादा 30 करोड़ हो सकती है। इसके मुताबिक देश का हर चौथा व्यक्ति इस महामारी की चपेट में आ चुका है। इस सर्वेक्षण से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी है।

सख्त मानकों के आधार पर सर्वे
दुनियाभर में अभी अमेरिका में संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा (2.70 करोड़) है। दूसरे नंबर भारत है। ये संकेत तब मिले हैं, जबकि पिछले हफ्ते एक निजी संस्था की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण की तुलना में यह सर्वेक्षण बहुत सख्त मानकों के आधार पर किया गया है।

आइसीएमआर का सीरो सर्वे
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

(आइसीएमआर) ने यह सीरो सर्वेक्षण किया है। आधिकारिक तौर पर वह गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में इसके नतीजे जारी करेगी। आधिकारिक तौर पर सर्वेक्षण के नतीजे नहीं जारी किए गए हैं, इसलिए सूत्र ने अपनी पहचान उजागर करने से इन्कार कर दिया। उसने यह भी नहीं बताया कि यह सर्वेक्षण कितने लोगों पर किया गया है।

क्या है सीरो सर्वेक्षण ?
आबादी में किसी बीमारी के प्रसार का आकलन करने के लिए सीरो यानी सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण किया जाता है। यह उस बीमारी के वायरस के खिलाफ पैदा होने वाली विशिष्ट एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाकर किया जाता है। सीरो सर्वेक्षण के लिए किसी क्षेत्र की आबादी के बीच से रैंडमली लोगों के रक्त के नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है।

15वां व्यक्ति पाया गया था संक्रमित
आइसीएमआर ने पिछले साल अगस्त और सितंबर में सीरो सर्वेक्षण किया था, जिसमें 10

साल से अधिक उम्र के 29,000 लोगों के रक्त के नमूनों की जांच की गई थी। आइसीएमआर ने तब कहा था कि हर 15वें व्यक्ति में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई थी। अधिक घनी आबादी वाले शहरी झोपड़पट्टी इलाके में हर छठे व्यक्ति में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का पता चला था।

दिल्ली में आधी से ज्यादा आबादी संक्रमित

दिल्ली सरकार ने इसी हफ्ते एक सीरो सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए हैं, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी की कुल दो करोड़ आबादी में से आधे से अधिक लोग कभी न कभी कोरोना महामारी की चपेट में आकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देश की निजी क्षेत्र की डायग्नोस्टिक कंपनी थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने सात लाख लोगों की जांच की थी। कंपनी के प्रमुख ने पिछले हफ्ते रायटर को बताया कि इस जांच में पता चला था कि 55 फीसद आबादी पहले ही संक्रमित हो चुकी होगी।

जिले में अब केवल एक कोविड अस्पताल

-उद्योग विहार (फरवरी 2021)-

गाजियाबाद। कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। शासन स्तर से कोरोना संक्रमण पर काबू पाए जाने की घोषणा कर दी गई है। जिसके बाद जिले में केवल एक अस्पताल को छोड़कर अन्य सभी निजी और सरकारी कोविड अस्पतालों को सामान्य कर दिया गया है। अब इन अस्पतालों में सामान्य मरीजों का उपचार भी हो सकेगा। पिछले 10 महीनों से कोरोना संक्रमण के खौफ से जुझ रहे सामान्य लोगों को अब खासी राहत मिलेगी। अब जिले में कोरोना संक्रमण का उपचार केवल एक ही अस्पताल में होगा। अन्य सभी अस्पतालों में अब सामान्य मरीज अपना उपचार करवा सकेंगे।

जिले में फिलहाल 9 निजी और 3 सरकारी कोविड अस्पताल थे। जिले के तीनों अस्पतालों में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। ईएसआई अस्पताल राजेंद्र नगर में पिछले लगभग दो महीनों से कोई मरीज भर्ती नहीं हुई है और संजय स्थित कंबाईड अस्पताल में पिछले 12 दिनों से कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ है। केवल संतोष अस्पताल में कुछ मरीज भर्ती हैं। जिले के निजी कोविड अस्पतालों में भी महज 23 मरीज ही भर्ती हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगभग एक सप्ताह पूर्व डीएम और शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। अपर मुख्य सचिव



अमति मोहन प्रसाद ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उनकी ओर से सीएमओ और डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि कोविड के घटते हुए संक्रमण से अब अस्पतालों की संख्या में बदलाव किया जा रहा है, जिससे कि सामान्य मरीजों के इलाज में सहूलियत मिले। पत्र में कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पांच दिन के अंदर इन अस्पतालों को दोबारा कोविड में बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस मामले में कंबाईड अस्पताल के सीएमएस डॉ. संजय तेवतिया का कहना है कि अस्पताल में सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। शासन की गाइड लाइन का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ती है तो एक आइसोलेशन वार्ड अलग से है, उसमें एचएफएनसी और वेंटीलेटर इंस्टाल कराया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड को रिजर्व रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सैनिटाइजेशन पहले ही कराया जा चुका है।

यूपी में वैक्सिनेशन होते ही 1800 स्वास्थ्यकर्मी हो गए 'लापता'

-उद्योग विहार (फरवरी 2021)-
कोविड वैक्सिनेशन का पहला राउंड पूरा होते ही 1800 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी लापता हो गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 26,292 कर्मचारियों का डाटा शासन को भेजा गया था लेकिन अब तक 24,289 हेल्थ वर्कर्स का ही पता चल सका है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्यकर्मियों का रिकार्ड बनाने में ही गड़बड़ी हुई है। कोरोना महामारी का टीका सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया है। शासन ने सभी जिलों से स्वास्थ्यकर्मियों की सूची मांगी थी। इसमें सरकारी और निजी अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया था। जिले से जो सूची शासन को भेजी गई थी, उसमें 26292 स्वास्थ्यकर्मी शामिल थे। संख्या के हिसाब से जिले प्रदेश में टाप 5 में शामिल था। पर जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो 1800 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का पता ही नहीं चल रहा। वैक्सिनेशन का पहला चरण पूरा हो गया है और अब तक 24289 स्वास्थ्यकर्मियों का ही रिकार्ड सत्यापित हो पाया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. आरएन सिंह ने कहा कि वैक्सिनेशन का पहला चरण पूरा होने के बाद करीब 1800 स्वास्थ्यकर्मी कम मिले। इससे संभावना है कि कई स्वास्थ्यकर्मियों के नाम दो या अधिक बार पोर्टल पर अपलोड हो गए थे। ये भी हो सकता है कि कई ऐसे लोगों के नाम भी अपलोड हुए हों जो इस मानक में नहीं आते थे।

पंचायत चुनाव: आरक्षण फार्मूले में देरी से दावेदार हो रहे परेशान

संभावित प्रत्याशियों ने खर्च पर लगायी लगाम, चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं इसे लेकर परेशान

-उद्योग विहार (फरवरी 2021)-
गाजियाबाद। पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय होने में हो रही देरी ने दावेदारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आरक्षण फार्मूला आने में अभी 15 दिन और लगेंगे लेकिन, सत्ता के गलियारों से आ रही खबरों के अनुसार, आरक्षण के चलते इस बार दिग्गजों को झटका लगना तय है। पंचायतीराज मंत्री के ही अनुसार, 70 प्रतिशत सीटों पर बदलाव हो सकता है। इसी लेकर संभावित प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभावने के लिये होर्डिंग, बैनर सहित दावतो व उपहार देने के सामान पर होने वाले खर्चों पर ब्रेक लगा दी है। जिले के 161 ग्रामों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की तैयारी जोरों पर चल रही है। गांव गांव दावेदारों की लंबी सूची हैं।

इन संभावित दावेदारों ने बीते वर्ष दीपावली पर कोविड-19 के दौर में मिठाईयो के अलावा उपहार बाँटे और जरूरतमंद लोगों को माँस्क, गमछे, साबुन, सैनेटाइज्ड के अलावा अन्य सामग्री वितरित की। होर्डिंग, बैनर के साथ ही सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार भी छेड़ दिया। उस बीच कुछ उम्मीदवार खुलकर सामने आ गए हैं तो वही कुछ दबी जुबान में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सभी की एक नजर आरक्षण के फार्मूला पर लगी हैं। उन्होने खर्चों पर आरक्षण के फार्मूले को लेकर ब्रेक लगा दिया है, हालांकि



ज्यादातर दावेदारों के पास बी-प्लान भी हैं कि मेरा नहीं आया तो तेरा सही।

एक दूसरे का समर्थन करने की भी बुनियाद तैयार की जा रही हैं। समर्थक भी असमंजस में हैं और कोई किसी को नाराज नहीं कर रहा हैं। लेकिन इंतजार जितना बढ़ता जा रहा हैं, दावेदारों की धड़कनें उतनी ही तेज होती जा रही हैं। 2015 में ग्राम पंचायतों में आरक्षण शून्य किया गया था। जो भी बड़ी वजह है कि

उम्मीदवारों की उलझन और ज्यादा बढ़ गई है।

किसानों के सहारे चुनाव की तैयारी
किसान आंदोलन और भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की आंखों में आंसुओं ने अचानक सभी पार्टियों के एजेंडे में किसानों को शामिल कर दिया है। पार्टियों ने किसानों के सहारे ही पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयंत चौधरी ने तो मथुरा की पंचायत में ऐलान कर दिया कि पंचायत

चुनाव में जिला पंचायत में हर एक सदस्य किसान को चुना जाए। उधर, कई अन्य पार्टियों ने भी तैयारी तेज कर दी है। किसान आंदोलन के बीच अब तेजी से पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, रालोद, बसपा ने तो तैयारी शुरू कर ही दी है। अब किसानों के मामले को लेकर अपना दल (एस), राष्ट्रीय एकता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी समेत कई पार्टियां भी सामने आ गई हैं। गांव-गांव प्रचार किया जा रहा है। किसानों के नाम पर गांव-गांव में अब संभावित प्रत्याशी तय किये जा रहे हैं।

भाजपा ने बहाई सक्रियता, लेकिन गांवों में घूमने का दूँड रही सहारा

भाजपा की ओर से अब जिला प्रभारियों की घोषणा कर कार्रवाई तेजी से की जा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में गजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर मंडल का जायजा ले चुके हैं। किसान आंदोलन के दौर में रालोद की किसान पंचायत के बाद तो किसानों की गांवों में गतिविधि तेज हो गई है। गांव-गांव अभियान शुरू कर दिया है। इन पार्टियों के नेताओं का कहना है कि अब तो पंचायत चुनाव में ही ताकत दिखानी है। साफ है कि बड़ी पार्टियों के साथ ही छोटी पार्टियों ने भी किसानों को एजेंडे में शामिल कर पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

U.P. MINIMUM WAGES GENERAL / ENGINEERING		U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES	PUNJAB MINIMUM WAGES	HARYANA MINIMUM WAGES	UTTARAKHAND MINIMUM WAGES
		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES
		01/04/20 TO 30/09/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020	1/3/2019	1/7/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
		BASIC + DA	BASIC + DA	BASIC + DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED		8625.00	10086.03	10574.06	14842.00	5850.00	8278.40	8776.83	9024.24	8331.00
SEMISKILLED		9487.50	11075.65	11631.46	16341.00	6162.00	8486.40	9556.83	*	8924.00
SEMISKILLED-A		*	*	*	*	*	*	*	9475.43	*
SEMISKILLED-B		*	*	*	*	*	*	*	9949.19	*
SKILLED		10627.50	12295.73	12688.87	17991.00	6474.00	8720.40	10453.83	*	9518.00
SKILLED A		*	*	*	*	*	*	*	10446.65	*
SKILLED B		*	*	*	*	*	*	*	10969	*
HIGHLY SKILLED		*	*	*	*	7774.00	*	11485.83	11517.45	*

40 करोड़ रु के सोने के घपले की चर्चा

-उद्योग विहार (फरवरी 2021)-

हापुड़। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए सराफा कारोबारियों के घपले की दर परत दर खुल रही है। पुलिस का दावा व बाजार में चर्चा है कि आरोपी सराफा ने बंधेल की करीब 80 किलो चनों पर होलमार्क लगाकर असली सोना बताकर महाराष्ट्र भेजा जहां वहां के लोगों ने इन्हें बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने इस गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया। चर्चा है 80 किलो के हिसाब से करीब 40 करोड़ रु का मामला बनता है। सराफा की गिरफ्तारी के बाद उसके घपले राज भी खुल रहे हैं। बाजार में चर्चा है कि लॉकडाउन में भी इस सराफा के यहां बाहर की पुलिस ने छापेमारी की और मामला 10 लाख रु में रफा दफा किया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी सराफा नकली होलमार्क लगाकर बंधेल के जेवर, शुद्ध सोने में बेचता था। महाराष्ट्र में कई शहरों में इस बंधेल का माल गया। जहां लोगों ने बैंक में गिरवी रखा और कर्ज ले लिया। करीब 80 किलो की बंधेल चैन शुद्ध सोने की बताकर महाराष्ट्र में भेजा गया है। 10 प्रतिशत के हिसाब से केवल इन चनों में 8 किलो सोना इस्तेमाल हुआ जबकि दाम 80 किलो सोने के लिए गए हैं। चर्चा है कि इस सराफा ने बाजार में कुछ दिनों पूर्व कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की बात भी कही थी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी सराफा बंधेल की चैन तैयार कराता था। लेकिन उसमें कुंदा शुद्ध सोने का बनवाकर लगवाकर होलमार्क लगा देता था। यदि कोई व्यक्ति चैन देखेगा तो कुंदा पर होलमार्क



लगा देख उसे शुद्ध सोने का मान लेगा। इस मामले में यही हुआ होगा। बैंक ने सोने की चीज मानकर उसे मानक के अनुरूप लोन जारी कर दिया लेकिन जांच में बंधेल पाए जाने पर मामला खुला। बता दें कि मुंबई (महाराष्ट्र) के थाना मोहोल पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर दो सराफा व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। उक्त दोनों ने मात्र 10 प्रतिशत सोने से बने आभूषणों पर 22 कैरेट का होलमार्क लगाकर बिक्री किया था। जिनके माध्यम से कुछ आरोपितों ने मुंबई के जिला सोलापुर के थाना मोहोल क्षेत्र स्थित बैंक व सराफा व्यापारियों से करीब दो करोड़ की ठगी की है। इस संबंध में 26 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया था। थाना मोहोल में तैनात एसआइ संतोष इंगले ने बताया कि मारुती प्रभाकर रेवनकर की सावलेश्वर में गंगा ज्वेलर्स

नाम से सोने के आभूषणों की दुकान है।

26 जनवरी को पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि थाना मोहोल क्षेत्र के पप्पू उर्फ डावल तंबोली व इस्माइल इनस ने 10 प्रतिशत सोने से बने आभूषण गिरवी रखकर करीब छह लाख रुपये की ठगी की है। जांच में पता चला कि आरोपितों ने कई अन्य सराफा व्यापारियों, लोगों व बैंकों में फर्जी आभूषणों को गिरवी रखकर करोड़ों रुपये की ठगी की है। इस मामले में सराफा गौरव अग्रवाल व उसके यहां काम करने वाले युवक अंकुर को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से बरामद किए गए आभूषणों की जांच करने पर पता चला कि वह 10 प्रतिशत सोने के बने हैं। इन आभूषणों पर 22 कैरेट का होलमार्क भी लगा है।

1 मार्च से खुलेंगे कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल, सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में शिक्षा विभाग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य में कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने का प्रस्ताव सीएम योगी की मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहीं, कक्षा एक से पांच तक के स्कूलों को एक मार्च से खोलने का प्रस्ताव है। अभी इस बारे में अंतिम निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले करीब एक साल स्कूलों में बंद चल रही पढ़ाई अब सरकार शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई फिर शुरू कराने पर विचार करने को कहा है। सीएम योगी ने पढ़ाई शुरू करने से पहले अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की स्थिति का

आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को कक्षा छह से आठ तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने और कक्षा एक से पांच तक के स्कूलों को एक मार्च से खोलने का प्रस्ताव भेजा है। अब सीएम योगी को इस पर अंतिम निर्णय लेना है। बता दें कि पिछले मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया था कि अब बच्चों को स्कूलों में कक्षा में भेजने के संबंध में विचार किया जाए। हर जिले में कोविड की स्थिति का आकलन के बाद ही पढ़ाई शुरू कराए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप ही स्कूलों में कक्षाएं चलाई जाएं। उन्होंने कहा कि दस दिन में स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई का संचालन शुरू कराने की तैयारी करें। सीएम योगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोविड-19 का टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित

किया जाए। इसी के साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस सिस्टम को सक्रिय रखा जाए। बता दें कि राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पहले से ही संचालित की जा रही हैं। अनएडेड प्राइवेट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश के तहत सभी एसोसिएशन से संबद्ध स्कूलों में कोविड 19 को लेकर जारी एसओपी का पालन कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। स्कूल खोलने की तारीख घोषित होते ही स्कूल खोल दिए जाएंगे। एसोसिएशन की ओर निर्णय लिया गया है कि सभी बोर्ड के स्कूलों में कक्षाएं अभी तीन घंटे के लिए ही संचालित की जाएंगी। सभी स्कूलों में सुबह दस बजे से एक बजे तक ब्लास लगेंगी। इसे लेकर सभी स्कूलों को तैयारियां करने को कहा गया है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की ओर से लिखित अनुमति ली जाएगी।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

<http://www.legalipl.com>

❖ LABOUR LAWS ❖ HR MANAGEMENT
❖ PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖ SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

📍 BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
📍 The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
☎ 9818036460
✉ legalipl243@gmail.com



सम्पादकीय

सियासत की खेती



सत्येंद्र सिंह

पहले करीब अठारह विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। फिर उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चलाने की घोषणा की। गणतंत्र दिवस के मौके पर लालकिले की घटना के बाद एक तरफ सरकार शरारती तत्त्वों से निपटने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ तमाम

विपक्षी दल सरकार को घेरने में जुटे हैं।

पंजाब और दिल्ली की सरकारों ने लालकिले की घटना के बाद गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए वकीलों की टीम और सहायता केंद्र गठित कर दिए हैं। उधर प्रियंका गांधी उस दिन आईटीओ पर ट्रैक्टर पलटने की वजह से मारे गए युवक के परिजनों से मिल कर मातमपुर्सी करने उनके घर पहुंचीं और घोषणा की कि किसानों का आंदोलन और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उस घटना के बाद कई विपक्षी दलों के नेता किसान नेताओं का हालचाल लेने गाजीपुर और सिंधु बार्डर पर भी हो आए हैं।

दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों की बढ़ती तादाद और उनके आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनके आसपास की जगहों पर कंटीले तारों, पक्की दीवारों और लोहे की कीलों से बाड़बंदी और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू कर दी, तो विपक्षी दलों को विरोध जताने का एक और मौका मिल गया। इस तरह लंबे समय से शिथिल पड़ी राजनीतिक पार्टियों को अपनी पक्षधरता साबित करने का मौका हाथ लग गया है।

केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को जैसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, तो विपक्षी दलों ने दम भरा है कि वे उन्हें वापस करा कर ही दम लेंगे। हालांकि फिलहाल इस मसले के सुलझने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही है, किसानों के समर्थन में साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोग भी उतर आए हैं।

मगर सरकार पर इन सबका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। किसान संगठन अपने दम पर कृषि कानूनों को वापस कराना चाहते हैं। शुरू से उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वे किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं लेंगे। इसलिए जो राजनेता उनसे मिलने भी जाते हैं, उन्हें वे अपना मंच साझा नहीं करने देते। ऐसे में राजनीतिक दलों का कृषि कानूनों का विरोध कितना प्रभावी साबित होगा, देखने की बात है।

यह सही है कि जब भी सत्तापक्ष के विरोध में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, तो उसे जो राजनीतिक दल पहले लपक कर अपने पक्ष में मोड़ लेता है, उसका जनाधार मजबूत हो जाता है। मगर इस आंदोलन का मिजाज कुछ अलग है। कह सकते हैं कि सही अर्थों में यह जनांदोलन है।

मगर विपक्षी दलों का प्रयास रहा है कि वे किसी तरह इसके मंच पर काबिज हो सकें। पर अब तक न तो उनकी कोई हिकमत काम आई है और न सत्तापक्ष के ही किसी आरोप की वजह से इस आंदोलन की पहचान किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकी है। इस तरह यह आंदोलन एक तरह से समूचे राजनीतिक नेतृत्व के नकार का भी प्रतीक बन गया है। यही वजह है कि किसान आंदोलन के दिनोंदिन और मजबूत होते जाने से सत्तापक्ष में बेशक कुछ घबराहट दिखाई देती है, पर विपक्षी दलों की लामबंदी की उसे कोई परवाह नजर नहीं आती।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक आंदोलन खींचना चाहते हैं टिकैत

मोदी सरकार द्वारा पास नया कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना नित्य नये रंग बदल रहा है। कभी इसमें खालिस्तानियों की इंट्री हो जाती है तो कभी टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले अपना एजेंडा लेकर आ जाते हैं। मोदी विरोधी नेताओं के लिए तो किसान आंदोलन किसी हानियामतल्ल से कम नहीं है। हर कोई किसानों की पीठ पर चढ़कर मोदी सरकार को चुनौती देने का ह्यपराक्रमल्ल कर रहा है। 26 जनवरी की हिंसा से पूर्व तक जिस किसान आंदोलन की कमान पंजाब और हरियाणा के किसान और जाट नेता संभाले दिखते थे, वह अब हाशिये पर चले गए हैं। उनकी जगह गाजीपुर बार्डर पर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के नेता राकेश टिकैत ने ले ली है, जो एक समय (26 जनवरी की घटना के बाद) धरना खत्म करने को तैयार हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर राकेश टिकैत पलट गए और मीडिया के सामने रोते हुए मोदी सरकार पर किसानों के साथ किए जा रहे कथित अत्याचारों के आरोपों की झड़ी लगा दी। राकेश टिकैत ने रोते हुए घोषणा कर दी कि अब वह तब ही जल ग्रहण करेंगे जब गांव से किसान ट्रैक्टर में जल लेकर आएंगे।

बस इसके बाद तो राकेश टिकैत की दसों उंगलियां घी में हो गईं। टिकैत के आंसू देखकर पश्चिमी यूपी के किसानों का दिल ऐसा पिघला कि राते के अंधेरे में ही किसानों का जत्था उनके गाँव और आसपास के जिलों से गाजीपुर बार्डर की तरफ कूच कर गया। मौके का फायदा उठाते हुए तमाम दलों के नेता भी टिकैत के सामने हाजिरी लगाने पहुंचने लगे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे इसके बाद तो सभी सियासी दलों में होड़ सी लग गई। किसान आंदोलन की कमान संभाले जिन नेताओं ने अब तक सियासतदारों को अपने मंच से दूर रखा था, वह सियासतदार टिकैत के सहारे मोदी सरकार पर हुक्का-पानी लेकर चढ़ाई करने लगे, टिकैत इन नेताओं के बगलगीर बने हुए थे। मोदी को गालियां दी जा रही थीं। नया कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन में अब मोदी विरोध के नाम पर देश का विरोध भी शुरू हो चुका था। कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंजाब, राजस्थान की सरकारें तक भूल गईं कि उनकी पहली वरीयता प्रदेश में अमन-चैन बनाए रखना है। ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल विधान सभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। आश्चर्य यह नहीं कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड़ा से लेकर ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता किसानों के पक्ष में ताल ठोक रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार और वित्त मंत्री रह चुके पी चिदंबरम भी सब कुछ जानते-समझते हुए नये कृषि कानून की मुखालफत कर रहे हैं।



टिकैत के आंसू देखकर पश्चिमी यूपी के किसानों का दिल ऐसा पिघला कि राते के अंधेरे में ही किसानों का जत्था उनके गाँव और आसपास के जिलों से गाजीपुर बार्डर की तरफ कूच कर गया। मौके का फायदा उठाते हुए तमाम दलों के नेता भी टिकैत के सामने हाजिरी लगाने पहुंचने लगे।

खैर, चिदंबरम के विरोध की वजह तो समझ में आती है, मोदी राज में ही उनको भ्रष्टाचार के चलते जेल जाना पड़ा था, जिसकी कसक आज भी उनकी बातों में दिखाई देती है, लेकिन शरद पवार क्यों सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं? यह सियासत के अलावा कुछ नहीं है। शरद पवार को अपनी सियासत बचाए रखने की चिंता ज्यादा है।

नये कृषि कानून के विरोध के नाम पर मचाए जा रहे हो-हल्ले का ही नतीजा है कि देश के बाहर बैठी शक्तियां भी सक्रिय हो गईं और किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर मोदी सरकार और देश को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रच रही हैं। यह सब जानते-बूझते हुए भी राकेश टिकैत चुप्पी साधे बैठे हैं। वह हर उस शाख के साथ खड़े होने से गुरेज नहीं कर रहे हैं जो उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं को परवान दे रहे हैं।

दरअसल, किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी में अपने विरोधियों को पटखनी देने के साथ-साथ सियासी जड़ों भी मजबूत करना चाहते हैं। राकेश टिकैत बहुत सोची-समझी रणनीति के तहत अपनी सियासी गोटियां बिछा रहे हैं। वह आंदोलन को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक खींचना चाहते हैं। टिकैत को यह पता है कि मोदी सरकार पूरी तरह से नया कृषि कानून वापस नहीं लेने वाली है। फिर भी टिकैत कानून वापस लेने की जिद्द करके समय पास कर रहे हैं।

टिकैत एक मझे हुए नेता हैं। उन्हें किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने का लम्बा अनुभव है। कई बार वह इसके चलते जेल भी जा चुके हैं। अपने पिता महेन्द्र टिकैत से इतर राकेश टिकैत राजनीति में भी हाथ अजमाने से परहेज नहीं करते हैं। वह कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता कभी हाथ नहीं लगी। इस बार भी राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी गोटियां बैठा रहे हैं। इसी के चलते टिकैत ने घोषणा कर दी है कि अक्टूबर तक उनका धरना-

प्रदर्शन जारी रहेगा, इसके बाद भी सरकार ने नया कृषि कानून वापस लेने की मांग नहीं मानी तो वह देश भर की यात्रा करेंगे। यानी नवंबर से टिकैत देश यात्रा के नाम पर अपनी सियासी जमीन तैयार करके योगी के बहाने मोदी को चुनौती देंगे। टिकैत को पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। मोदी अगर केन्द्र की सत्ता पर काबिज हैं तो इसका श्रेय यूपी को जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भरपूर समर्थन मिला था। राकेश इसी तिलिस्म को तोड़ना चाहते हैं।

राकेश टिकैत ने कभी राजनीति से परहेज नहीं रखा। साल 2007 में पहली बार उन्होंने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा जिसमें वह हार गये थे। उसके बाद टिकैत ने 2014 में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के टिकैट पर चुनाव लड़ा, पर वहाँ भी उनकी बुरी हार हुई। राकेश टिकैत को करीब से जानने वाले कहते हैं कि राकेश को यह पता है कि उनकी दो ताकत हैं किसान और खाप नामक सामाजिक संगठन, जिसमें टिकैत परिवार की काफी इज्जत है। अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए ताल ठोकने में लगे टिकैत 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली गेट तक आ गये थे। उस समय भी किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था।

उस समय टिकैत के आलोचकों ने कहा था कि भोले-भाले किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने यह स्टंट अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाएँ पूरी करने के लिए किया, जिसका किसानों के हित में कोई नतीजा नहीं निकला। राकेश टिकैत जाट समुदाय से आते हैं जिसके बारे में आम धारणा यही है कि यह बिरादरी लामबंद होकर वोटिंग करती है, इसीलिए तमाम दलों के नेता राकेश टिकैत के पीछे लगे हैं। इसीलिए तमाम दलों के नेता उनके यहां दस्तक दे रहे हैं।



TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD

<http://www.takshakindia.com>

- ❖ EVENTS MANAGEMENT
- ❖ PR MANAGEMENT
- ❖ ARTISTS MANAGEMENT

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

चक्का जाम : लाल किला, जामा मस्जिद आईटीओ और दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन बंद

इंटरचेंज जारी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

-उद्योग विहार (फरवरी 2021)-

नई दिल्ली। देशभर में आज जारी किसानों के चक्का जाम के महेजनर दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए आज दिल्ली में 50 हजार से ज्यादा पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को लालकिले से लेकर दिल्ली की सीमाओं पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों के चलते ऐहतियातन अब तक अपने 10 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी बंद कर दी है। हालांकि, इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली मेट्रो के जिन स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी बंद की गई है उनमें- मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, विश्वविद्यालय, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपथ, केंद्रीय सचिवालय, खान मार्केट और नेहरू प्लेट शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, किसान संगठनों ने आज देशभर में चक्का जाम का आह्वान किया है। किसान संगठन देशभर में आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। इसको देखते हुए दिल्ली में लाल किला, आईटीओ समेत सभी बॉर्डरों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ चप्पे-चप्पे पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। हालांकि, किसानों ने दिल्ली चक्का जाम से बाहर रखा है, लेकिन पुलिस सुरक्षा में कोई चूक नहीं करना चाहती है। इसके साथ ही सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, भोपुरा बॉर्डर, दिल्ली-नोएडा बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, और हरियाणा के पलवल में भी सुरक्षा कड़ी की गई है। सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के क्रम में जहां अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है वहीं, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, कंटीले तार तथा सड़कों पर नुकली कीलें लगाई गई हैं। प्रदर्शनकारी किसानों



ने शुक्रवार को ये ऐलान किया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में शनिवार को चक्का जाम नहीं होगा। किसान देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से तीन घंटे के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर चक्का जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि 'चक्का जाम' के दौरान एंबुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। 'चक्का जाम' शनिवार को दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं,

गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शनिवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन इन दोनों राज्यों के किसानों को किसी भी समय दिल्ली बुलाया जा सकता है। टिकैत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसान छोटे समूहों में जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपेंगे।

गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध के चलते राजधानी दिल्ली से लगी

गाजीपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन आज 73वें दिन भी जारी है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों की संख्या में पिछले दिनों कमी आई थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद एक बार फिर से आंदोलन को बढ़ी संख्या में किसानों का समर्थन मिलने लगा।

एलईडी लाइट रखरखाव नई कंपनियों को देने की तैयारी को लेकर खड़ा हुआ विवाद

-उद्योग विहार (फरवरी 2021)-

गाजियाबाद। एलईडी लाइट लगाने वाली कंपनी द्वारा मांगे गए करीब 65 करोड़ रुपये के देने का मामला अभी फाइनल नहीं हो पाया है, वहीं अनुबंध खारिज किए बिना एलईडी लाइट अनुरक्षण का कार्य दो अन्य कंपनियों को देने की तैयारी शुरू हो गई है। इन दोनों ही कंपनियों के नाम पहले ही तय हो चुके हैं। निगम के एक अधिकारी ने दोनों ही कंपनियों को अनुरक्षण का कार्य देने के लिए हस्ताक्षर की मुहिम शुरू की थी मगर कई अधिनस्थ अधिकारियों ने इस पत्रावली पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसी को लेकर विवाद पैदा हो गया है।

निगम अधिकारियों का कहना है कि जब एलईडी लाइट लगाने वाली कंपनी और निगम के बीच अनुबंध अभी खारिज नहीं हुआ है, कंपनी ने नगर निगम पर कोर्ट केस किया हुआ है, उस पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में एलईडी लाइट के अनुरक्षण का कार्य किसी अन्य कंपनी को सौंपना खतरनाक है।

नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि अगर एलईडी लाइट लगाने वाली कंपनी कार्य नहीं करेगी तो क्या शहर में अंधेरा होने दिया जाए।

उनका तर्क है कि हमारी कोशिश है कि शहर की लाइट का अनुरक्षण करने के लिए अलग फर्म हो। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है।

किसी निर्धारित कंपनियों को ठेका नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर निगम में ही अंदरखाने इसको लेकर विवाद पैदा हो गया है।

कृषि बिल विरोध के समर्थन में आई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां

-उद्योग विहार (फरवरी 2021)-

गाजियाबाद। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बार्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय हस्तियों से समर्थन मिलने का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस बारे में भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपने ही अंदाज में कहते हैं कि कौन है रिहाना, खलीफा और ग्रेटा थमबर्ग जिसने हमारे आंदोलन को समर्थन दिया है 'मुझे क्या पता, करा होगा, मैं क्यों उन्हें जानूँ।' हालांकि विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय कलाकारों एवं कार्यकर्ताओं जैसी हस्तियों की ओर से आंदोलन को मिले समर्थन का उन्होंने स्वागत किया है। कमजोर आंदोलन ने फिर पकड़ ली रफतार दिल्ली में गणतंत्र दिवस को हुई हिंसा के बाद गाजीपुर बार्डर पर आंदोलनरत किसानों को जब हटाने के लिये प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गत माह 28 जनवरी को जब प्रशासन ने घेराबंदी शुरू की उसी दौरान उनकी भावुकता में आँसू आसूँओं ने आंदोलन को फिर हवा मिल गयी है। अब देश के किसानों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के आने से सोशल मीडिया पर पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है। राकेश टिकैत को बताया गया कि अमेरिकी पॉप गायिका

राकेश टिकैत बोले- कौन हैं रिहाना, खलीफा, और ग्रेटा थमबर्ग? मैं नहीं जानता

रिहाना, वयस्क फिल्मों की कलाकार मिया खलीफा, स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थमबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है तो सिसौली में जन्में किसान नेता ने कहा, 'मुझे क्या पता, करा होगा, मैं क्या जानूँ उन्हें!' 'विदेशी कर रहा समर्थन तो क्या है समस्या?' राकेश टिकैत ने कहा, 'कोई विदेशी अगर समर्थन कर रहा है तो क्या दिक्कत है, कुछ ले-दे थोड़ी न रहा है।' गाजीपुर बार्डर पर प्रदर्शनकारियों से मिलने की असफल कोशिश करने वाले 15 संसद सदस्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सांसद अवरोधक के दूसरी ओर जमीन पर बैठे क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, 'बैरिकेडिंग लगा रखी है है-नै। उन्हें आणा था, वे वहीं बैठ जाते। वे उन्चै बैठ जाते, हम है-नै बैठे थे।' टिकैत ने बताया कि उन्होंने गाजीपुर मिलने आने की कोशिश करने वाले 15 सांसदों में से किसी से बात नहीं की, उन्हें प्रदर्शनकारियों से बात नहीं करने दी गई।

8वीं बटालियन एनडीआरएफ के 250 जवानों को लगा कोरोना का टीका



-उद्योग विहार (फरवरी 2021)- गाजियाबाद। कमला नेहरू नगर स्थित आठवीं बटालियन एनडीआरएफ में हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा उद्घाटन किए हुए हॉस्पिटल में टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान जवानों को कोरोना का टीका लगताया गया। बटालियन के मीडिया प्रभारी वसंत पावडे ने बताया कि यह टीकाकरण कार्यक्रम सुबह 10:00 बजे से शुरू किया गया है। सबसे पहला टीका डॉ. राहुल कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एनडीआरएफ को लगाया गया। जनता को टीका

लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए टीकाकरण के बाद एक सेल्फी प्यांटी भी बना लिया गया है, जहां टीका लगवाने के बाद सेल्फी ले रहे हैं। जिन्होंने अभी तक टीकाकरण कराया है, वह काफी उत्साहित है।

डॉ. अमित मुरारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कमांडेंट पीके तिवारी समेत 250 पदाधिकारी तथा जवानों को टीका लगाया जा रहा है। यहां पर लगभग 1300 जवानों को टीकाकरण किया जाएगा 28 दिन के बाद इसका दूसरा टीका लगाया जाएगा। बटालियन कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया कि

एनडीआरएफ द्वारा जनवरी 2020 से ही कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा लॉकडाउन के दौरान शहर में सैनिताइजेशन कर मास्क, सैनिताइजर, सुखा राशन तथा पका हुआ भोजन भी वितरित किया गया। इन फ्रंट लाइन जवानों को आज कोविशिल्ड वैक्सीन दी जा रही है।

उन्होंने सभी देशवासियों को अपील की है कि इस वैक्सीन का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। हमारे लिए हर्ष की बात है कि यह वैक्सीन अपने देश में बनाई गई है। यह वैक्सीन अपना नंबर आने पर सभी लोग जरूर लगवाएं।